भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3159
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

पीएमयूवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शन

†3159. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत से नवम्बर, 2023 तक इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शनों, विशेषकर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किए गए एलपीजी कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विगत दो वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के अंतर्गत कितने सिलेंडरों की रीफिलिंग की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस संख्या को बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किए गए रीफिलिंग का ब्यौरा क्या है, जिसे एक रिफिल, दो रिफिल, तीन रिफिल और चार या अधिक रिफिल के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): पूरे देश में गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के थाने जिले में 0.48 लाख कनेक्शनों सहित देश में 9.59 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए गए हैं। सभी पीएमयूवाई कनेक्शन सक्रिय रखे जाते हैं। पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए सक्रिय एलपीजी कनेक्शनों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख): महाराष्ट्र के थाने जिले में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.42 लाख रीफिल और 2022-23 में 2.47 लाख रीफिल लिए।

(ग): पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पूरे देश में एलपीजी पंचायतों, सोशल मीडिया अभियानों, कनेक्शनों के वितरण हेतु सार्वजनिक समारोह तथा जनजागरूकता अभियानों आदि का आयोजन किया है। सरकार ने एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को अधिकतम 12 रीफिल/प्रति वर्ष के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम रीफिल पर 200/- रुपए की निर्धारित राजसहायता, अक्तूबर, 2023 से प्रतिवर्ष अधिकतम 12 रीफिल के लिए निर्धारित राजसहायता बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर करना, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 कि.ग्रा. वाले सिलेंडर को 5 कि.ग्रा. के सिलिंडर में बदलने का विकल्प, अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को अधिकतम 3 निशुल्क रीफिल दिया जाना आदि शामिल हैं। रीफिल बुकिंग में आसानी के लिए अनेक साधन अर्थात इंटरएक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), वॉ सएप, वितरक के फोन पर सीधे फोन करना, ई-कामर्स प्लेटफार्म्स, ओएमसी मोबाइल एप्लीकेशन, ओएमसीज वैब पोर्टल्स आदि उपलब्ध करवाए गए हैं।

(घ) महाराष्ट्र में उन पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के दौरान कनेक्शन लगाने के समय दी गई रीफिल सहित एक रीफिल, दो रीफिल्स, तीन रीफिल्स और चार अथवा अधिक रीफिल्स लिए हैं:

(लाख में)

राज्य	एक रीफिल	दो रीफिल्स	तीन रीफिल्स	चार और अधिक रीफिल्स
महाराष्ट्र	5.29	6.77	7.65	26.43

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक

'पीएमयूवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शन' के बारे में दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3159 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या	
राज्य/संघ शासित प्रदेश	**दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,444
आं प्रदेश	5,12,433
अरुणाचल प्रदेश	49,245
असम	44,14,012
बिहार	1,07,35,289
चंडीगढ़	659
छत्तीसगढ	34,92,160
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15,033
दिल्ली	1,42,024
गोवा	1,265
गुजरात	38,42,970
हरियाणा	7,67,162
हिमाचल प्रदेश	1,40,776
जम्मू और कश्मीर कें शासित प्रदेश	12,45,232
झारखंड	36,46,176
कर्नाटक	37,57,307
केरल	3,41,210
कें शासित प्रदेश लद्दाख	11,094
लक्ष ीप	309
म य प्रदेश	82,27,217
महाराष्ट्र	48,89,709
मणिपुर	2,02,029
मेघालय	2,14,851
मिजोरम	33,595
नगालैंड	91,806
ओडिशा	53,20,752
पुदु ेरी	14,835
पंजाब	12,83,827
राजस्थान	69,26,442
सि म	13,795
तमिलनाडु	37,03,824
तेलंगाना	11,52,806
त्रिपुरा	2,83,503
उत्तर प्रदेश	1,75,00,658
उत्तराखंड	4,96,431
प म बंगाल	1,23,70,935

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

*****